सुरक्षा, शांति और समृद्धि

सजग भारत

01-15 अक्टूबर, 2023 वर्ष-1 अंक-13

निःशुल्क प्रति

दो साल में वामपंथी उग्रवाद से

मुक्त होगा भारत

वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र में उल्लेखनीय गिरावट

नागरिकों की मृत्यु में **68%** की कमी

वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में **52%** की कमी

सुरक्षा बलों की मृत्यु में **72%** की कमी

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची विकास की रोशनी

अनुक्रमणिका

सिर्फ आतंकवाद ही नहीं बल्कि इसके पूरे इकोसिस्टम... 9
वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक दौर में 10
जनजातीय युवाओं के लिए हैं अपार संभावनाएं 12
माओवादी क्षेत्रों में सरकार के प्रयास से पुनर्जीवित हुआ लोकतंत्र 14
वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची विकास की रोशनी 16
हर जवान की हौसला अफजाई 19
आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का समय आ गया है 22
चार वर्षों में आई वामपंथी उग्रवाद में कमी 26

विशेष रिपोर्ट

05 दो साल में वामपंथी उग्रवाद से मुक्त होगा भारत
18 एशियाई खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
24 शहीदों के सपनों का भारत

संपादक की कलम से...

बालाजी श्रीवास्तव

महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

> केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने आने वाले दो वर्षों में भारतभूमि को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नक्सलवाद मानवता के लिए अभिशाप है और सरकार इसके सभी प्रारूपों के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है।

देश की शांति और कानून व्यवस्था के लिए जरूरी है कि हर प्रकार की अलगाववादी शक्तियों को नष्ट किया जाए। हाल के वर्षों में केंद्र सरकार ने इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार आतंकवाद और उग्रवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। सभी केंद्रीय सशस्त्र बलों, सुरक्षा एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों को ऐसी उग्रवादी ताकतों के दमन के लिए सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस बलों और सुरक्षा एजेंसियों के बेहतर समन्वय से वामपंथी उग्रवाद भारत में अब अपने अंतिम दिन गिन रहा है।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्देशन में केंद्र सरकार ने 2015 में 'वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' को मंजूरी दी थी। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले से अधिक एक्टिव मोड में आकर काम करने लगा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कई ऑपरेशन चलाए। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल केवल उग्रवादियों को खत्म करने के लिए ही मुहिम नहीं चलाता है, बल्कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों के लिए आम जीवन भी सुलभ कराता है। पिछले पांच वर्षों में देश में इन क्षेत्रों की सुरक्षा की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

हाल ही में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए राजधानी दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने आने वाले दो वर्षों में भारतभूमि को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नक्सलवाद मानवता के लिए अभिशाप है और सरकार इसके सभी प्रारूपों के उन्मूलन के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। पिछले चार दशकों में, वर्ष 2022 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा और हत्याओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। आंकड़े बताते हैं कि नक्सल प्रभावित राज्यों में हिंसक घटनाओं में वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2022 में 77% प्रतिशत की कमी आई है।

आप लोग 'सजग भारत' के सभी अंकों को सराह रहे हैं। हमारा यह प्रयास कैसा है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें sajag-bharat@bprd.nic.in पर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें नई राह दिखाती हैं, साथ ही हमारा हौसला भी बढ़ाती हैं।

जय हिन्द!

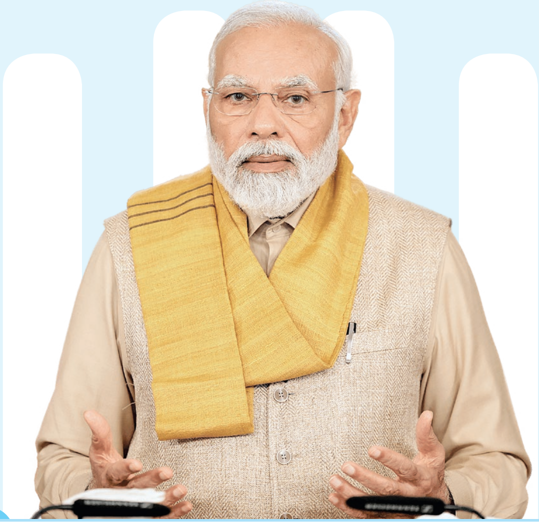

देशभर के हमारे परिवारजनों ने खादी की खरीदारी का जो नया रिकॉर्ड बनाया है, उससे पता चलता है कि यह किस प्रकार जनभावना का एक सशक्त प्रतीक बन गई है। मुझे विश्वास है कि खादी के प्रति यह लगाव नित नए रिकॉर्ड बनाता रहेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत के विजन को नया बल मिलेगा।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

काउन्टर टेररिज्म के एप्रोच में जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटजी और जीरो टॉलरेंस एक्शन को अपनाकर आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना होगा।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत आज ग्लोबल ग्रोथ इंजन बन चुका है। आईएमएफ के अनुसार 2024 में भी भारत 6.3% की विकास दर के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

श्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

Flagged off the Swachhta Freedom Run 4.0 with immense pride and enthusiasm! As we embark on this journey of #SwachhtaHiSeva, let us remember that cleanliness is not just a responsibility but a symbol of our commitment to a healthier and more beautiful India.

Shri Nisith Pramanik
MoS, Ministry of Home Affairs

सिक्किम राहत शिविरों और मेडिकल कैंपों में आपदा प्रभावित लोगों से संपर्क, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। यहां एनडीआरएफ, आईटीबीपी और भारतीय सेना निरंतर बचाव कार्यों में लगी हुई है।

श्री अजय मिश्रा
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 7 अक्टूबर, 2023 को उत्तराखंड के देहरादून में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

गृह मंत्रालय
भारत सरकार

दो साल में वामपंथी उग्रवाद से मुक्त होगा भारत

वह दिन दूर नहीं जब देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो जायेगा। वामपंथी उग्रवाद दिन प्रतिदिन सिकुड़ता जा रहा है। सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ चरमपंथियों पर अंतिम हमले के लिए तैयार रहें, आने वाले दिनों में देश इससे मुक्त हो जायेगा।

श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही श्री नरेन्द्र मोदी ने नासूर बन चुकी कई समस्याओं को स्थायी समाधान की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक नासूर वामपंथी उग्रवाद रहा है। बीते नौ वर्षों के दौरान उग्रवाद की घटनाओं में आई कमी को देखते हुए इसे संघवाद बेहतर कामों की परिणति कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने त्रिसूत्रीय रणनीति बनाकर काम करना शुरू किया, जिसका परिणाम यह रहा कि देश के कुछ हिस्सों में हो रहा वामपंथी उग्रवाद अब सिकुड़ रहा है।

केंद्र सरकार का मानना है कि जब तक वामपंथी उग्रवाद की समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, तब तक देश और इससे प्रभावित राज्यों का पूर्ण विकास संभव नहीं है। गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद के खतरे से निपटने के लिए साल 2015 से एक 'राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' पर काम कर रहा है। नीति में हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता बरतने की बात कही गई है।

खास बात यह भी है कि 6 अक्टूबर, 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ वामपंथी उग्रवाद की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बेखौफ़ अंदाज में कहा कि केवल दो सालों में इसका समूल नाश कर दिया जाएगा। इसके लिए तमाम एजेंसियों को तयशुदा कार्ययोजना के तहत करने का एक बार

वामपंथी उग्रवाद को लेकर प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की नीति शुरू से ही बेहद सख्त रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह नक्सलवाद को 'मानवता के लिए अभिशाप' बताते रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार वामपंथी उग्रवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्रालय, तमाम सुरक्षा एजेंसियों और राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा अगले दो वर्षों में इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है।

फिर निर्देश दिया गया। विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु गृह मंत्रालय द्वारा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों के साथ बैठक और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित मॉनीटरिंग की जाती है।

केंद्र सरकार राज्यों की पुलिस के आधुनिकीकरण और उनके प्रशिक्षण के लिए सुरक्षा संबंधी खर्च, योजना और विशेष बुनियादी ढांचा योजना के तहत पैसे भी देती है। वहीं, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के विकास के लिए, भारत सरकार ने कई विकासात्मक पहलें की हैं जिनमें 17,600 किलोमीटर सड़क को मंजूरी देना शामिल है। केंद्र की नीति के मुताबिक, गृह मंत्रालय सीएपीएफ बटालियनों की तैनाती, हेलीकॉप्टर और यूएवी के प्रावधान, इंडिया रिजर्व बटालियन, विशेष इंडिया रिजर्व बटालियन की मंजूरी देकर क्षमता निर्माण और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में राज्य सरकारों की मदद की जाती है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों की नियमित मांग पर सरकार द्वारा 'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण' की अम्ब्रेला स्कीम की उप-योजना के रूप में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत सुरक्षा से संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्यों को धन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत 971 करोड़ रुपये की परियोजनाओं/कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन स्वीकृत कार्यों में 250 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन शामिल हैं, जिनमें से 204 का निर्माण किया जा चुका है।

'पुलिस स्मृति दिवस' के उपलक्ष्य पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को बरकरार रखते हुए सख्त कानून बनाये हैं और पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 'पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन' की स्थापना करके विश्व का सर्वश्रेष्ठ आतंकवादरोधी बल बनने की दिशा में काम किया है। पिछले एक दशक में हमारे बहादुर पुलिसकर्मियों के कारण आतंकवाद, उग्रवादी हमलों, नक्सलवाद और नस्लीय हिंसा में इसके सर्वोच्च स्तर से 65 प्रतिशत की कमी आई है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए एक अलग से प्रभाग बनाया हुआ है। इसे नाम दिया गया है-वामपंथी उग्रवाद प्रभाग। इसमें माओवाद के बारे में सभी

राज्यों के साथ बैठक में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा की गई घोषणाएं

- **सभी नागरिकों को 5 किलोमीटर के भीतर मिलेगी बैंकिंग सुविधा।**
- **एकलव्य मॉडल के अंतर्गत खोले जाने वाले स्कूलों की गति होगी तेज।**
- **सड़क एवं टेलीकॉम कनेक्टिविटी में सुधार, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और शिक्षा पर रहेगा जोर।**
- **सुरक्षा के उपायों के साथ-साथ विकास के कार्यों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करना रहेगी प्राथमिकता।**

संदर्भ सी पी आई (माओवादी) तथा विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत आतंकवादी संगठनों की अनुसूची में शामिल अन्य वामपंथी उग्रवादी संगठनों के संदर्भ में हैं। सरकार ने हिंसा छोड़ने तथा बातचीत के लिए आगे आने के लिए वामपंथी उग्रवादियों से अनुरोध किया है। इस अनुरोध को उन्होंने अस्वीकार्य कर दिया है क्योंकि वे सत्ता हथियाने के साधन के रूप में हिंसा में विश्वास करते हैं। इसके परिणामस्वरूप भारत के अनेक भागों में हिंसा की निरंतर घटनाएं हुई हैं। आदिवासियों जैसे निर्धन और पिछड़े वर्ग इस हिंसा के शिकार हो रहे हैं। अनेक उदार बुद्धजीवी माओवादी विद्रोह के सिद्धान्त, जो हिंसा को महिमा मंडित करता है तथा सत्ता हासिल करने के लिए सैन्य सिद्धांत को अपनाने में विश्वास करता है, के सही स्वरूप को समझे बिना माओवादी प्रचार का शिकार बन जाते हैं। वर्ष 2004 से 2022 के मध्य भारत के विभिन्न भागों में वामपंथी उग्रवादियों द्वारा लगभग 8,625 लोगों की हत्या की गई है। मारे गए अधिकांश नागरिक आदिवासी होते हैं जिनको बेरहमी से यातना दिए जाने और मारे जाने से पूर्व अक्सर 'पुलिस मुखबिर' की संज्ञा दी जाती है। वास्तव में, ये आदिवासी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिनके हित का समर्थन करने का माओवादी दावा करते हैं, भारत राष्ट्र के विरुद्ध सी.पी.आई. (माओवादी) के कथित 'प्रोट्रेक्टेड पीपल्स वार' के सबसे बड़े शिकार हुए हैं।

प्रभावित राज्यों में आधारभूत संरचना पर जोर

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क आवश्यकता योजना 8 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़िशा और उत्तर प्रदेश के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में सड़क संपर्क में सुधार करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग

वामपंथी उग्रवाद में उल्लेखनीय गिरावट

- वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 52% की कमी
- वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं की सूचना देने वाले जिलों में 53 % की कमी
- नागरिकों की मृत्यु में 68% की कमी
- सुरक्षा बलों की मृत्यु में 72% की कमी
- वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं की सूचना देने वाले पुलिस थानों में 62% की कमी

मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

इस योजना में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में 5,362 किमी. लंबी सड़कों के निर्माण की परिकल्पना की गई थी जिसमें से 5,136 किमी. लंबी सड़कों का निर्माण कर लिया गया है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए सरकार ने इन क्षेत्रों में 20 अगस्त, 2014 को मोबाइल टॉवर्स लगाए जाने का अनुमोदन किया था और परियोजना के प्रथम चरण में 2,343 मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं। परियोजना के द्वितीय चरण में 2,542 मोबाइल टावर्स लगाए जा रहे हैं।

सिविक एक्शन कार्यक्रम से सुधरी है स्थिति

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम वैयक्तिक संपर्क के माध्यम से सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच दूरी को कम करने और स्थानीय लोगों के समक्ष सुरक्षा बलों का मानवीय चेहरा प्रदर्शित करने के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की 'अम्ब्रेला योजना' की उप-योजना के रूप में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह योजना अपने लक्ष्य हासिल करने में बहुत सफल रही है। इस योजना के अंतर्गत स्थानीय लोगों के कल्याण हेतु विभिन्न नागरिक गतिविधियां चलाने के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को निधियां जारी की जाती हैं।

वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई अब महत्वपूर्ण चरण में

श्री अमित शाह के अनुसार, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के विकास के लिए भारत सरकार ने कई विकासात्मक पहल की हैं। जिनमें 17,600 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी देना शामिल है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में लोगों के वित्तीय समावेशन के लिए कई डाकघर, बैंक शाखाएं, एटीएम और बैंकिंग संवाददाता खोले गए हैं। वामपंथी उग्रवाद के खतरे के खिलाफ लड़ाई अब एक महत्वपूर्ण चरण में है और सरकार जल्द से जल्द इस खतरे को मामूली स्तर तक कम करने को लेकर आशावादी है। भारत सरकार का यह मानना है कि विकास और सुरक्षा संबंधी पहलों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण से वामपंथी उग्रवाद की समस्या से सफलतापूर्वक निपटा जा सकता है। तथापि यह स्पष्ट है कि वामपंथी उग्रवादी कम विकास जैसे मुख्य कारणों का सार्थक तरीके से निराकरण करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वे विद्यालय भवनों, सड़कों, रेल मार्गों, पुलों, स्वास्थ्य अवसंरचना, संचार सुविधाओं आदि को व्यापक रूप से निशाना बनाते हैं। ये अपनी पुरानी विचारधारा को कायम रखने के लिए अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में लोगों को हाशिये पर रखना चाहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव ने देश के अनेक भागों में विकास की प्रक्रिया को दशकों पीछे धकेल दिया है। इसे सिविल समाज तथा मीडिया द्वारा समझे जाने की आवश्यकता है, ताकि वामपंथी उग्रवादियों पर हिंसा छोड़ने, मुख्य धारा में शामिल होने तथा इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए दवाब बनाया जा सके कि 21वीं सदी के भारत की सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक सोच और आकांक्षाएं माओवादी दृष्टिकोण से पूरी नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त हिंसा और विनाश पर आधारित कोई विचारधारा ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सफल नहीं हो सकती जिसमें शिकायतों के निराकरण के लिए वैध मंचों की व्यवस्था है। ■

सिर्फ आतंकवाद ही नहीं, बल्कि इसके पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की जरुरत

कोई नया आतंकी संगठन खड़ा ही न हो पाए इसके लिए सभी एंटी-टेरर एजेंसियों को Ruthless Approach को अपनाना होगा।

ब्यूरो

आतंकवाद और आतंकी संगठनों के लिए रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरी क्रूरता के साथ इन्हें कुचलना होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह जब नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित तीसरे दो.दिवसीय आतंकवाद निरोधक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तो इसी संदर्भ में उन्होंने तमाम सुरक्षा एजेंसियों को काम करने के लिए कहा। सीधे शब्दों में उनका कहना था कि आतंकवाद निरोधक एजेंसियों को ऐसा कठोर रुख अपनाना होगा कि देश में नए आतंकवादी संगठन पनप ही न सके। आतंकवाद निरोधक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने यह भी कहा कि न केवल आतंकवाद, बल्कि आतंकवादियों के पूरे इको-सिस्टम को नष्ट करना होगा। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लिए गए सख्त फैसलों से क्रिप्टोकरेंसी, हवाला, आतंकी वित्तपोषण, संगठित अपराध गिरोह और नार्को-टेरर लिंक से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

केंद्र सरकार जब सख्त निर्णय लेती है तो उसके दूरगामी प्रभाव होते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने बताया कि सरकार के कड़े फैसलों से जम्मू-कश्मीर, नक्सल प्रभावित इलाकों और पूर्वोत्तर में हिंसा कम करने में बड़ी सफलता मिली है। पिछले 5 वर्षों में सरकार ने कई बड़े डेटाबेस तैयार किए हैं। केंद्र और राज्य की सभी एजेंसियों को उनका बहुआयामी उपयोग करना चाहिए तभी हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सफल होंगे। हमें जांच, अभियोजन, रोकथाम और कार्रवाई के लिए इस डेटाबेस का उपयोग करना है।

5 अक्टूबर को इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती और कोई भी राज्य अकेले आतंकवाद का सामना नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर इस बुराई को जड़ से खत्म करना होगा। गृह मंत्री ने दो दिवसीय सम्मेलन के हर सत्र में 5 कार्रवाई योग्य बिंदु बनाकर उन्हें केन्द्रीय गृह मंत्रालय को भेजने का सुझाव दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित दो-दिवसीय आतंकवाद-निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया।

श्री शाह ने कहा कि एनआईए, एटीएस और एसटीएफ का काम सिर्फ जांच करना नहीं है, बल्कि इन्हें जांच के दायरे से बाहर निकलकर अलग तरीके से सोचते हुए आतंकवाद पर प्रहार करने की दिशा में भी काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ग्लोबल से गांव तक और देश के विभिन्न राज्यों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ काम करने की जरूरत है। केंद्र और राज्यों की सभी एजेंसियों को बहुआयामी और एआई आधारित तकनीक का उपयोग करना चाहिए। इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 99.93 फीसदी यानी 16,733 पुलिस स्टेशनों में सीसीटीएनएस लागू हो चुका है। ई-कोर्ट से 22 हजार अदालतें जुड़ गई हैं। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में 90 लाख से अधिक फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड दर्ज हैं। इंटिग्रेटेड मॉनिटरिंग ऑफ टेररिज्म के तहत यूएपीए रजिस्टर्ड मामलों की मॉनिटरिंग के लिए 22 हजार आतंकवादी मामलों का डाटा उपलब्ध है। डेटाबेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर्स के तहत लगभग 1 लाख ह्यूमन ट्रैफिकर्स का डाटा उपलब्ध है। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर के तहत 14 लाख से अधिक अलर्ट का डाटा उपलब्ध है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर 28 लाख से अधिक कंप्लेंट का डाटा उपलब्ध है। इसके अलावा एनआईए का राष्ट्रीय स्तर का टेररिज्म डेटाबेस भी उपलब्ध है।

श्री अमित शाह ने कहा, सभी केंद्रीय और राज्य-स्तरीय आतंकवाद-निरोधी एजेंसियों के लिए एक समान ट्रेनिंग मॉडयूल होना चाहिए। इसके माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की कार्यपद्धति में एकरूपता लाई जा सकेगी। इस दिशा में एनआईए और आईबी को पहल करने के लिए कहा गया है। ■

वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक दौर में

ब्यूरो

देश की सुरक्षा के मसले पर जब सरकार निश्चय कर लेती है, तो उसे हर हाल में पूरा किया जाता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने देश में वापमंथी उग्रवाद को पूरी तरह से खत्म करने का प्रण ले लिया है। गृह मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों को पूरी तरह से काम करने के लिए कहा हुआ है। सटीक कार्ययोजना के साथ इस पर काम चल रहा है। तभी स्वयं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद को केवल 2 वर्षों में पूरी तरह से खत्म करने की बात की है।

6 अक्टूबर को नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ वामपंथी उग्रवाद की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में केन्द्रीय मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केन्द्रीय गृह सचिव, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक, केन्द्र सरकार के सचिव, राज्यों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसकी अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 2019 के बाद से अब तक निर्वात क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है, हमने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 195 नए शिविर स्थापित किए हैं, इसके साथ ही 44 नए शिविर और स्थापित किये जायेंगे। श्री शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती, विकास का युक्तिकरण और निर्वात क्षेत्र में शिविर स्थापित करना सरकार की प्राथमिकताएं हैं। वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हुए क्षेत्रों में लगातार निगरानी बनाए रखने की जरूरत है, जिससे वहां इस समस्या का पुनः प्रवर्तन न हो सके। उन्होंने कहा कि जिन

प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ निश्चय और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी राज्यों के सहयोग से 2022 और 2023 में इस समस्या के खिलाफ बड़ी सफलताएं प्राप्त हुई हैं।

क्षेत्रों से इस समस्या को खत्म किया जा चुका है वहां से वामपंथी उग्रवादी अन्य राज्यों में शरण न लें, इसकी मॉनीटरिंग करने की भी जरूरत है।

श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने 2014 से ही वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई है। हमारी शून्य सहिष्णुता की नीति के परिणामस्वरूप 4 दशक में सबसे कम हिंसा और हत्याएं 2022 में दर्ज की गई हैं। 2005 से 2014 के कालखंड के मुकाबले 2014 से 2023 के बीच वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा में 52 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है, मृत्यु में 69, सुरक्षाबलों की मृत्यु में 72 और नागरिकों की मृत्यु में 68 प्रतिशत की कमी आई है। श्री अमित शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद को अगले 2 सालों में पूरी तरह समाप्त कर देंगे। सरकार ने वर्ष 2014 से ही वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। साल 2019 के बाद से नक्सलियों के इलाके तेजी से कम हुए हैं। इसी बात से समझा जा सकता है कि केंद्रीय बलों के 195 नए शिविर नक्सलियों से लड़ाई के लिए बनाए गए हैं। ऐसे 44 शिविर और बनाए जाएँगे, जहाँ से नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ी जाएगी।

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, श्री शाह ने यह भी कहा कि वर्ष 2022

> वामपंथी उग्रवाद के वित्तीय पोषण पर प्रहार करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय सभी राज्यों की एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वामपंथी उग्रवाद के वित्तीय पोषण को रोकने के लिए प्रभावित राज्यों को अपने यहां नागरिक और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर प्रयास करने की जरूरत है।
>
> **श्री अमित शाह,** केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

में पिछले चार दशकों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा और मौतों की सबसे कम घटनाएं देखी गईं। उन्होंने कहा, दो साल में देश से वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नक्सलवाद मानवता के लिए अभिशाप है और हम इसके सभी रूपों में उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद के वित्तीय पोषण पर प्रहार करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय सभी राज्यों की एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वामपंथी उग्रवाद के वित्तीय पोषण के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सभी प्रभावित राज्यों को अपने यहां नागरिक और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2017 में वामपंथी उग्रवाद के पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया था, इसे अब बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है।

वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित राज्यों में विकास को गति देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। सड़क निर्माण, दूरसंचार, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में विकास को गति देने के लिए विशेष अवसंरचना योजना के तहत 14,000 से अधिक परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें से 80 प्रतिशत से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित राज्यों को 3,296 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। राज्य खुफिया शाखाओं और वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित राज्यों के विशेष सुरक्षा बल और दस्तों को मजबूत करने के लिए 992 करोड़ रुपये की विशेष अवसंरचना योजना परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। सरकार ने 9 वर्षों में सुरक्षा संबंधी व्यय को पहले की तुलना में लगभग दोगुना बढ़ाने का काम किया है।

पिछले पांच वर्षों में देश में वामपंथी सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में 'वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' को मंजूरी दी थी। नीति में सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास हस्तक्षेपों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने आदि को शामिल करते हुए एक बहु-आयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है। ■

जनजातीय युवाओं के लिए हैं अपार संभावनाएं

वामपंथी उग्रवाद के विचार को खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने जनजातीय युवाओं से जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि ये युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे न तो खुद गलत रास्ते पर जाएं और न ही दूसरों को जाने दें।

ब्यूरो

हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 200 जनजातीय युवा एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत जनजातीय युवाओं से संवाद किया। इस दौरान उनकी समस्याओं को सुना और सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित राज्यों में विकास को गति देने के लिए कई कदम उठा रही है। सड़क निर्माण, दूरसंचार, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में विकास को गति देने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत 14000 से अधिक परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें से 80 प्रतिशत से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित राज्यों को 3296 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। किलेबंद पुलिस स्टेशन के निर्माण, राज्य खुफिया शाखाओं और वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित राज्यों के विशेष बलों को मजबूत करने के लिए 992 करोड़ रुपये की विशेष अवसंरचना परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने 9 वर्षों में सुरक्षा संबंधी व्यय को पहले की तुलना में लगभग दोगुना बढ़ाने का काम किया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों में अपने निहित स्वार्थ के लिए भ्रांति फैलाई जा रही है कि देश में जनजाति समुदाय के बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। हिंसा से रोजगार नहीं मिल सकता, विकास और आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए समाज की मुख्यधारा से जुड़ना जरूरी है। जो लोग वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर, सड़क और अन्य जरूरी सुविधाएं नहीं आने देना चाहते, वे युवाओं के उज्जवल भविष्य की राह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि ये युवाओं की ज़िम्मेदारी है कि वे न तो खुद गलत रास्ते पर जाएं और न ही दूसरों को जाने दें। वामपंथी उग्रवादी और उनकी विचारधारा देश के विकास और उज्ज्वल भविष्य के विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद के विचार को खत्म करने में जनजातीय युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि जनजातीय युवाओं को देश भ्रमण के बाद अपने गांव वापस जाकर सबको बताना चाहिए कि देश आज हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और जनजातियों के लिए हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं किसी का जन्मस्थान महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि जीवन

में किए गए कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। केवल पुरुषार्थ से ही धन, विद्या और सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। जनजातीय युवाओं से उन्होंने कहा कि वे तय करें कि उन्हें जीवन में क्या बनना है और उसके लिए पुरुषार्थ करें।

आंकड़े बताते हैं कि जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम में 2006-07 से 2022-23 तक 25,880 जनजातीय युवाओं ने भाग लिया। पिछले 9 वर्षों, 2014-15 से 2022-23 तक 20,700 युवाओं ने इसमें भाग लिया और 2019-20 से 2022-23 तक पिछले 4 वर्षों में 10,200 युवाओं ने भाग लिया। इस वर्ष 5,000 युवक और युवतियां भाग ले रहे हैं। पहले हर साल 2,000 प्रतिभागी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे, जिसे अगस्त, 2019 के बढ़ाकर 4,000 और 2022 में 5,000 प्रतिभागी प्रति वर्ष कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में 2006-07 से 2022-23 तक 25,880 जनजातीय युवाओं ने भाग लिया। पिछले 9 वर्षों, 2014-15 से 2022-23 तक 20,700 युवाओं ने इसमें भाग लिया और 2019-20 से 2022-23 तक पिछले 4 वर्षों में 10,200 युवाओं ने भाग लिया। इस वर्ष 5,000 युवक और युवतियों भाग ले रहे हैं। पहले हर साल 2,000 प्रतिभागी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे, जिसे अगस्त, 2019 के बढ़ाकर 4,000 और 2022 में 5,000 प्रतिभागी प्रति वर्ष कर दिया गया है।

अपनी बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। यह गर्व की बात है कि एक आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 200 करोड़ रुपये की लागत से देश भर में 10 आदिवासी संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि आदिवासी युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे न तो गलत रास्ते पर चलें और न ही दूसरों को ऐसा करने दें। श्री अमित शाह ने कहा कि आदिवासी युवाओं को घर जाकर सबको बताना चाहिए कि आज देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और आदिवासियों के लिए हर क्षेत्र में पर्याप्त अवसर हैं।

दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय पिछले 15 वर्षों से जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम चला रहा है। यह कार्यक्रम युवा मामले व खेल मंत्रालय के अधीन नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसमें वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के अंदरूनी हिस्से से जनजातीय युवक और युवतियों को देशभर के प्रमुख शहरों और महानगरों के भ्रमण पर ले जाया जाता है। इसके माध्यम से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं की आकांक्षा को बढ़ाया जाता है। वामपंथी उग्रवादियों द्वारा सरकार के विरुद्ध फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का मुकाबला किया जाता है। इन क्षेत्रों के युवाओं को विकास गतिविधियों और औद्योगिक उन्नति से अवगत कराकर तथा उन्हें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदनशील बनाया जा रहा है। साथ ही इन क्षेत्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति विश्वास को पहले से अधिक मजबूत किया जा रहा है। ऐसे आयोजनों के बाद जब ये जनजातीय युवा अपने क्षेत्रों में जाते हैं, तो ये सरकार की प्रमुख विकास और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अपने लोगों को जागरूक करते हैं। इसके माध्यम से सबको विश्वास में लेकर विकास की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित की जा रही है। ■

जो लोग वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर, सड़क और अन्य जरूरी सुविधाएं नहीं आने देना चाहते, वे युवाओं के भविष्य की राह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य

- सरकार के खिलाफ सीपीआई (माओवादियों) के दुष्प्रचार का मुकाबला करना।
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं की आकांक्षाओं को बढ़ाना।
- उन्हें नौकरी के अवसरों, विकास और औद्योगिक उन्नति से परिचित कराना।
- भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत के प्रति सराहना को बढ़ावा देना।
- लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास को मजबूत करना।
- आदिवासी युवाओं को विकास और कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूक करना।
- विभिन्न क्षेत्रों के साथियों के साथ भावनात्मक संबंध विकसित करना।

माओवादी क्षेत्रों में सरकार के प्रयास

जिन क्षेत्रों में पहले माओवादियों का अच्छा-खासा प्रभाव था, लोग अपने घरों से बाहर निकलने में हिचकते थे। उन क्षेत्रों में आम जनता अब सरकार की नीतियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल खासकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की योजनाबद्ध कार्यकुशलता से लोकतांत्रिक पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। सख्त सुरक्षा उपायों को लागू करने के साथ-साथ विकास को प्रोत्साहित करने की दो-आयामी रणनीति प्रभावी साबित हो रही है।

ब्यूरो

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में, बांसागुड़ा और हीरापुर गांवों को जोड़ने वाला 17 साल पुराना पुल थालपेरू नदी पर बना हुआ है। यह एक ऐसा पुल जिसे कभी माओवादियों के खौफ के कारण लोग उपयोग में नहीं लाते थे। डर के कारण कई ग्रामीणों को आंध्र प्रदेश की ओर पलायन करना पड़ा, क्योंकि दो दर्जन से अधिक गांवों को जोड़ने के लिए बनाए गए पुल का उपयोग नहीं हो पा रहा था।

यह परिस्थिति अब अतीत की बातें हो गईं। केंद्र सरकार की नीतियों और बांसागुड़ा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के शिविर खुलने से एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरूआत हुई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अब इस क्षेत्र में गश्त कर रही है। लोग अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। नई आशा का संचार हुआ और लोकतांत्रिक पर्व में सभी अपनी अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। माओवादी भय के कारण पिछले 17 वर्षों से इन क्षेत्रों में यह दिखाई नहीं पड़ रहा था। बस्तर क्षेत्र में, जिसमें सात जिले शामिल हैं, पहले माओवादियों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में अचूक सुरक्षा के साथ 126 नए मतदान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। यह कदम न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बहाली का प्रतीक है, बल्कि स्थानीय समुदायों का विश्वास फिर से हासिल करने में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस के सफल प्रयासों का भी प्रतीक है। इन नए मतदान केंद्रों में से चालीस को

से पुनर्जीवित हुआ लोकतंत्र

रणनीतिक रूप से गांवों के भीतर रखा गया है, ताकि लोगों को मतदान करने के लिए यात्रा न करनी पड़े, जो कि सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

अत्याधिक सावधानी के साथ किए गए इस पूरे ऑपरेशन का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि इन क्षेत्रों में लोकतांत्रिक प्रथाएं वास्तव में व्यवहार्य हैं, जिससे माओवादी गतिविधियों के किसी भी डर को दूर किया जा सके। सुरक्षा की इस भावना को सुदृढ़ करने के लिए, 26 नए सीएपीएफ शिविर स्थापित किए गए हैं। चांदामेथा में एक निवासी 40 वर्षों में पहली बार अपना वोट डालेंगे। कुछ माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में, जहां चुनौतियाँ अधिक हैं, मतदान दलों को सीएपीएफ की कड़ी निगरानी में भेजा जाएगा, यहां तक कि ग्रामीणों की सुरक्षित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हेलीकॉप्टरों का भी उपयोग किया जाएगा। सुकमा जिले में, छह गांवों के निवासी चुनावी प्रक्रिया में भाग लेंगे, जो 20 वर्षों में मतदान करने का उनका पहला अवसर है।

इन विकासों का व्यापक प्रभाव भय में उल्लेखनीय कमी और इन समुदायों का मुख्यधारा में पुनः एकीकरण है, जो राज्य पुलिस के सहयोग से सीएपीएफ की रणनीतिक तैनाती से सुगम हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को उनकी क्षमता बढ़ाने और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हेलीकॉप्टरों, यूएवी के प्रावधान के साथ-साथ सीएपीएफ बटालियनों की तैनाती और इंडिया रिजर्व बटालियन (आईआरबी) और स्पेशल इंडिया रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी) की मंजूरी ने खुद माओवादी तत्वों में भय की भावना पैदा कर दी है। विशेष अवसंरचना योजना के तहत गढ़वाले पुलिस स्टेशनों के निर्माण और राज्य खुफिया शाखाओं और विशेष बलों को मजबूत करने के लिए 992 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस प्रयास के परिणामस्वरूप 2014 से 536 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों का निर्माण हुआ है, जो इस अवधि से पहले निर्मित 66 से काफी अधिक है।

इंटेलिजेंस ब्यूरो और मजबूत राज्य खुफिया एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी सुरक्षा बलों को माओवादी नेतृत्व के प्रमुख लोगों को बेअसर करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण रही है। साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने संबंधित मामलों की जांच और अभियोजन में तेजी लाने के लिए वामपंथी उग्रवाद के लिए अलग से प्रभाग की स्थापना की है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर वित्तीय जांच माओवादी रसद आपूर्ति लाइनों को बाधित करने में सहायक रही है। लोगों का दिल जीतने के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के विकास के लिए भारत सरकार की पहल में परियोजनाओं का व्यापक दायरा शामिल है। इनमें सड़क नेटवर्क का विस्तार शामिल है, जिसमें पिछले नौ वर्षों में 12,100 किमी सड़कें स्वीकृत और 10,300 किमी का निर्माण किया गया है। दूरसंचार कनेक्टिविटी के प्रयासों से 3,000 से अधिक मोबाइल टावरों की स्थापना हुई है, जबकि अन्य 13,000 टावरों की स्थापना अभी चल रही है। डाक नेटवर्क का भी विस्तार किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के 3 किमी के भीतर कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 4,903 डाकघर खोले गए हैं। पिछले आठ वर्षों में 30 सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद जिलों में 955 शाखाएं और 839 एटीएम स्थापित किए गए हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में, सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 252 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को मंजूरी दी है, जिनमें से 163 पिछले चार वर्षों में चालू हो गए हैं। विशेष केंद्रीय सहायता योजना ने 14,000 से अधिक परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत से अधिक पूरी हो चुकी हैं, प्रभावित राज्यों को 3,296 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

इन व्यापक उपायों से वामपंथी हिंसा और इसके भौगोलिक प्रसार में उल्लेखनीय कमी आई है। 2010 की तुलना में 2022 में वामपंथी हिंसा की घटनाओं में 76% की गिरावट आई है, साथ ही परिणामी मौतों में 90 प्रतिशत की कमी आई है। इसके अलावा, माओवादी प्रभाव वाले क्षेत्र में भारी कमी आई है, भौगोलिक विस्तार 2010 में 96 जिलों से घटकर 2022 में केवल 45 रह गया है। ■

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों

देश के जो हिस्से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, वहां की नियति हिंसा और चीत्कार ही वहां की नियति बन चुके थे। लेकिन सरकार की नीति और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की मुस्तैदी से अब वहां विकास की रोशनी पहुंच चुकी है। हिंसा की जगह लोग विकास की बात कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।

ब्यूरो

कभी वामपंथी उग्रवाद का गढ़ रहे छत्तीसगढ़ के सुकमा में जब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रवास कर लोगों की समस्याओं को जाना और उसे दूर करने के निर्देश दिए। प्रवास के दौरान श्री अमित शाह ने स्थानीय स्कूलों, अस्पतालों एवं भंडारगृह का दौरा किया। इस दौरान बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों से जहां उनका हालचाल पूछा वहीं सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं को भी जाना। श्री अमित शाह पोटकपल्ली गांव में जब स्कूली बच्चों से बात कर रहे थे तब उनका शिक्षक रूप दिखा। इस दौरान श्री शाह ने स्पष्ट किया था कि छोटे से इलाकों में सिमटे नक्सलियों के खिलाफ अंतिम प्रहार का समय आ गया है और जल्द ही देश को दशकों पुराने नक्सलवाद से मुक्ति मिल जाएगी।

वापमंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए भारत सरकार ने विशेष रूप से 'राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' तैयार की है। इसमें सरकार की बहु-आयामी रणनीति शामिल है, जिसमें सुरक्षा, विकास, आदिवासियों/स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करना और बेहतर धारणा प्रबंधन आदि शामिल हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2010-11 से वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में सिविक एक्शन प्लान (सीएपी) लागू किया जा रहा है। योजना के तहत स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न नागरिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बीते कुछ वर्षों से इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं।

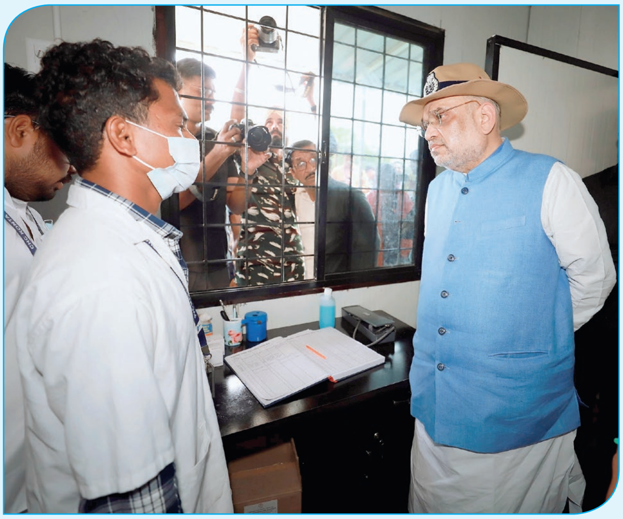

सीआरपीएफ से स्थानीय लोगों में विश्वास जाग्रत हुआ और विकास की नई शुरूआत हुई। इन क्षेत्रों के लोग अब अपनी कई बुनियादी और छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए सीआरपीएफ से संपर्क करते हैं। ऐसे कार्यों से सबके सामने सीआरपीएफ का मानवीय चेहरा आता है। सुरक्षा के साथ लोगों में विश्वास जगाने का काम किया जा रहा है, जो लगातार स्थानीय आबादी के दिल और दिमाग को जीतकर उन्हें वामपंथी उग्रवादियों के चंगुल से दूर रख रही है।

में पहुंची विकास की रोशनी

चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से सीआरपीएफ ने स्थानीय आबादी की बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद की है। इन प्रयासों ने सामुदायिक जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा दिया है, जिससे क्षेत्र की भलाई पर स्वामित्व की भावना को बढ़ावा मिला है। गतिविधियों ने इन क्षेत्रों में सैनिकों की वैकल्पिक और रचनात्मक उपस्थिति प्रदान करके वामपंथी चरमपंथी समूहों के प्रभाव का मुकाबला करने में मदद की है।

मानव संसाधन विकास योजना के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण, हस्तशिल्प/कुटीर उद्योगों से संबंधित कौशल प्रशिक्षण, युवाओं के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण, करियर परामर्श, कोचिंग आदि और स्कूली बच्चों के लिए अध्ययन सामग्री प्रदान करना शामिल है। इन प्रयासों ने गरीब ग्रामीणों को रोजगार योग्य कौशल से सुसज्जित किया है, जिससे बेरोजगारी कम हुई है। उन्हें चरमपंथी समूहों में शामिल होने से रोका गया है। स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता में व्यापक वृद्धि हुई है, जिससे वे सरकार के प्रति अधिक सहयोगी बन गए हैं।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, जल संचयन संरचना एवं फल देने वाले पौधों आदि की व्यवस्था करती है। इसके अलावा सुअर पालन, बकरी पालन तथा मुर्गी पालन आदि के लिए सहकारी फार्म विकसित करने हेतु ग्रामीणों को उचित सहायता प्रदान करती है; जिससे आजीविका बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा में मदद मिलती है। जैसे-जैसे स्थानीय आबादी आर्थिक रूप से स्थिर हो रही है और सरकार के प्रयासों पर भरोसा करना शुरू कर रही है, चरमपंथी विचारधाराओं और भर्ती प्रयासों की अपील भी कम हो रही है।

सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत स्ट्रीट लाइटिंग और सोलर लैंप के प्रावधान सहित गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों की सुरक्षा में सुधार हुआ है और वे उन गतिविधियों में शामिल होने में सक्षम हुए हैं।

सामुदायिक भागीदारी के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरने के

अलावा, खेल और शारीरिक गतिविधियों ने उन ग्रामीणों के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान दिया है, जो अब तक इस तरह के अवसर से वंचित थे। खेल सुविधाएं और उपकरण प्रदान करके तथा खेल टूर्नामेंट आयोजित करके सीआरपीएफ ने कम तनाव के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया है, जिससे गतिहीन जीवन से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का मुकाबला करना आसान हो गया है। खेलों को बढ़ावा देने से स्थानीय प्रतिभाओं की पहचान और पोषण हुआ है, सामाजिक एकजुटता आई है और अंततः उग्रवाद से ध्यान हट गया है।

सिविक एक्शन प्रोग्राम भी एक पहल है, जिसका उद्देश्य बूढ़े, गरीब और विकलांग लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान क्षतिग्रस्त हुई छतों आदि की मरम्मत के लिए सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा विभिन्न आवश्यक वस्तुएं, यानी बर्तन, ट्रांजिस्टर, छाते, कपड़े / कंबल, साइकिलें आदि भी प्रदान की जा रही हैं। मानवीय राहत की इन गतिविधियों ने गरीब ग्रामीणों की आर्थिक असुरक्षा को कम किया है। ■

एशियाई खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

ब्यूरो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 10 अक्टूबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एशियाई खेल 2022 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल को संबोधित किया। उन्होंने एथलीटों से भी बातचीत की। भारत ने एशियाई खेल 2022 में 28 स्वर्ण पदक सहित 107 पदक जीते। यह महाद्वीपीय बहुस्पर्धी आयोजन में जीते गए पदकों की कुल संख्या के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

प्रधानमंत्री ने कहा' आपने इतिहास रचा है। इस एशियन गेम्स के आंकड़े भारत की सफलता के गवाह हैं। एशियाई खेलों में यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यह व्यक्तिगत संतुष्टि की बात है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।' प्रधानमंत्री ने याद करते हुए कहा कि यह एक सुखद संयोग है कि एशियाई खेलों का शुभारंभ 1951 में इसी स्टेडियम में हुआ था। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि एथलीटों द्वारा दिखाए गए साहस और दृढ़ संकल्प ने देश के हर कोने को एक जश्न के माहौल में बदल दिया है। 100 से अधिक पदकों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किए गए परिश्रम को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पूरा देश गर्व की भावना का अनुभव कर रहा है। उन्होंने कोचों और प्रशिक्षकों को भी उनके योगदान के लिए बधाई दी और फिजियो और अन्य अधिकारियों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने सभी एथलीटों के माता-पिता को नमन किया और परिवारों द्वारा किए गए योगदान और बलिदान पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने कहा, 'प्रशिक्षण मैदान से मंच तक, माता-पिता के समर्थन के बिना यह यात्रा असंभव है।'

> **9 साल पहले की तुलना में खेल का बजट भी 3 गुना बढ़ाया जा चुका है। हमारी टॉप्स और खेलो इंडिया स्कीम गेमचेंजर साबित हुई हैं।**
>
> **श्री नरेन्द्र मोदी,** प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने महिला एथलीटों द्वारा किए गए योगदान पर गर्वपूर्वक कहा कि यह भारत की बेटियों की क्षमताओं को उजागर करता है। उन्होंने बताया कि जीते गए सभी पदकों में से आधे से अधिक महिला एथलीटों ने हासिल किए और यह महिला क्रिकेट टीम ही थी, जिसने सफलताओं का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने कहा कि बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा पदक महिलाओं ने जीते हैं। उन्होंने प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए महिला एथलेटिक्स टीम की भी सराहना करते हुए कहा, 'भारत की बेटियां, ट्रैक और फील्ड इवेंट में नंबर वन से कम में मानने को तैयार नहीं हैं।'■

हर जवान की हौसला अफजाई

ब्यूरो

12 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड के पार्वती कुंड और गुंजी गए, तो वहां देश की रक्षा में तैनात सेना, सीमा सड़क संगठन और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों से मिले। सभी का हालचाल पूछा और उनके जोश को हाईजोश में बदल दिया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड के पार्वती कुंड और गुंजी में सेना, सीमा सड़क संगठन और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के समर्पित कर्मियों के साथ बातचीत की। श्री मोदी ने रेखांकित किया कि उनकी भावना और समर्पण पूरे देश को प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने सैनिकों, कलाकारों और स्वयं सहायता समूहों के साथ अपनी बैठकों का भी उल्लेख किया और सुरक्षा, समृद्धि और संस्कृति के स्तंभों के मिलने पर खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उन्होंने कहा 'हमारी सरकार उत्तराखंड के लोगों की प्रगति और जीवन को आसान बनाने के लिए पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ काम कर रही है।' प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के साथ अपने लंबे जुड़ाव और निकटता को याद किया।

इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि पार्वती कुंड और गुंजी में सेना, बीआरओ और आईटीबीपी के समर्पित कर्मियों के साथ बातचीत की। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उनकी अटूट सेवा वास्तव में सराहनीय है। उनकी भावना और समर्पण पूरे देश को प्रेरित करता है।

इसी दिन प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगभग 4,200 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पार्वती कुंड में पूजा और दर्शन किए। उस समय कहा था कि मैंने प्रत्येक भारतीय के अच्छे स्वास्थ्य और विकसित भारत की मजबूती का संकल्प लेते हुए प्रार्थना की। मैंने आशीर्वाद मांगा कि उत्तराखंड के लोगों की सभी आकांक्षाएं पूरी हों।

एकत्र जनसमूह को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा पर उत्तराखंड के लोगों के अभूतपूर्व प्यार, स्नेह और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया और कहा, 'यह स्नेह की गंगा बहने की तरह था।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैद्यनाथ धाम में जय बद्री विशाल के उद्घोष से गढ़वाल राइफल्स के जवानों का जोश और उत्साह बढ़ता है और गंगोलीहाट के काली मंदिर में घंटियों की ध्वनि कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों में नए साहस का संचार करती है। मानसखंड में प्रधानमंत्री ने बैद्यनाथ, नंदादेवी, पूर्णागिरि, कसारदेवी, कैंचीधाम, कटारमल, नानकमत्ता, रीठा साहिब और अनेक अन्य मंदिरों का उल्लेख किया, जो इस भूमि की भव्यता और विरासत को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 'जब भी मैं आपके बीच उत्तराखंड में होता हूं, हमेशा खुद को धन्य समझता हूं।'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'उत्तराखंड के हर गांव ने भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैन्य कर्मियों को जन्म दिया है।' प्रधानमंत्री ने बताया कि 'वन रैंक वन पेंशन' योजना के तहत पूर्व सैनिकों को अब तक 70,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है, जिससे पूर्व सैनिकों के 75,000 से अधिक परिवारों को अत्यधिक लाभ हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास, सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। पिछली सरकारों के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की कमी की ओर इशारा करते हुए, प्रधानमंत्री ने अवसंरचना विकास को लेकर पड़ोसी देशों द्वारा भूमि हड़पने के उनके डर के बारे में बात की। प्रधानमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे अवसंरचना विकास के बारे में बात करते हुए कहा, 'न तो न्यू इंडिया किसी चीज से डरता है, न ही यह दूसरों में डर पैदा करता है।' पिछले 9 वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों में 4,200 किमी से अधिक सड़कें, 250 पुल और 22 सुरंगें निर्मित की गई हैं। प्रधानमंत्री ने आज की परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि रेलवे को सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचाने की योजना पर काम चल रहा है।■

विश्व भर की कई संसदीय प्रथाओं का एक अनूठा संगम

ब्यूरो

राजधानी दिल्ली के द्वारका में नवनिर्मित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित पी20 शिखर सम्मेलन का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। इस दौरान जी20 के सदस्यीय देशों के सभापतियों को भी संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस और विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। वे यशोभूमि अधिवेशन केंद्र में जी20 के सदस्य देशों की संसदों के पीठासीन सभापतियों के नौवें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पी20 के नौवें सम्मेलन की थीम 'एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य के लिए संसद' है।

प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधियों को संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के हाल के निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों में 30 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों में से लगभग 50 प्रतिशत महिलाएँ हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा 'भारत आज हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। हमारी संसद द्वारा हाल ही में लिया गया निर्णय हमारी संसदीय परंपरा को और समृद्ध करेगा।'

प्रधानमंत्री ने भारत की संसदीय परंपराओं में नागरिकों के अटूट विश्वास को रेखांकित किया और इसकी विविधता और जीवंतता को श्रेय दिया। प्रधानमंत्री ने कहा 'हमारे यहां हर धर्म के लोग हैं। सैकड़ों प्रकार के भोजन, रहन-सहन, भाषाएं और बोलियां हैं।' उन्होंने बताया कि भारत में लोगों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए 28 भाषाओं में 900 से अधिक टीवी चैनल हैं, लगभग 200 भाषाओं में 33 हजार से अधिक विभिन्न समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लगभग 3 बिलियन उपयोगकर्ता हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत में सूचना के विशाल प्रवाह और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के स्तर पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा '21वीं सदी के इस विश्व में, भारत की यही जीवंतता, अनेकता में एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह जीवंतता हमें हर चुनौती से लड़ने और हर कठिनाइयों का समाधान हल करने के लिए प्रेरणा देती है।'

विश्व की परस्पर जुड़ी प्रकृति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संघर्ष और टकराव से भरी दुनिया किसी के हित में नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि एक विभाजित दुनिया मानवता के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकती है। यह समय शांति, भाईचारे और साथ मिलकर चलने का है। यह सबके विकास और खुशहाली का समय है। हमें वैश्विक अविश्वास के संकट से उबरना होगा और मानव-केंद्रित सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें विश्व को एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना से देखना होगा। वैश्विक निर्णय लेने में व्यापक भागीदारी के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके पीछे अफ्रीकी संघ को जी20 में शामिल करने का प्रस्ताव था जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकार कर लिया।

> भारत की संसदीय परंपराओं पर, देशवासियों के अटूट विश्वास की एक और बड़ी वजह है, जिसे आपको जानना और समझना बहुत अहम है। ये शक्ति है, हमारी विविधता, हमारी विशालता, हमारी वाइब्रेंसी। हमारे यहां हर आस्था के लोग हैं। सैकड़ों तरह का खानपान, सैकड़ों तरह का रहन-सहन हमारी पहचान है।
>
> **श्री नरेन्द्र मोदी,** प्रधानमंत्री

संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए जनभागीदारी से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा 'मेरा हमेशा से मानना रहा है कि सरकारें बहुमत से बनती हैं, लेकिन देश सर्वसम्मति से चलता है। हमारी संसदें और यह पी-20 फोरम भी इस भावना को मजबूत कर सकते हैं।' प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि बहस और विचार-विमर्श के माध्यम से इस दुनिया को बेहतर बनाने के प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे।■

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को जीवन देगी नौका सेवा

ब्यूरो

भारत के नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांकेसनथुरई के बीच 40 वर्ष बाद नौका सेवा शुरू हुई। इससे दोनों देशों के बीच नई सुविधाओं का आगाज होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अक्टूबर को वीडियो संदेश के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और श्रीलंका राजनयिक और आर्थिक संबंधों की दिशा में एक नए अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं। नागपट्टिनम और कांकेसनथुरई के बीच नौका सेवाओं का शुभारंभ दो देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में अपनी श्रीलंका यात्रा को याद किया जब दिल्ली और कोलंबो के बीच सीधी उड़ान शुरू की गई थी। तत्पश्चात प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीलंका से तीर्थ नगरी कुशीनगर में पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के आने का उत्सव भी मनाया गया था। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि चेन्नई और जाफना के बीच सीधी उड़ान वर्ष 2019 में आरंभ की गई थी और अब नागपट्टिनम और कांकेसनथुरई के बीच नौका सेवा इस दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है।

भारत और श्रीलंका के बीच संस्कृति, वाणिज्य और सभ्यता के साझा इतिहास को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नागपट्टिनम और इससे जुड़े हुए आसपास के शहर श्रीलंका सहित कई देशों के साथ समुद्री व्यापार के लिए जाने जाते रहे हैं और प्राचीन तमिल साहित्य में भी पूंपुहार के ऐतिहासिक बंदरगाह को प्रमुख केन्द्र बताया गया है। उन्होंने पट्टिनप्पलाई और मणिमेकलाई जैसे संगम युग के साहित्य के बारे में भी अपने विचार रखे, जिसमें दोनों देशों के बीच नौका सेवा और समुद्री जहाजों के परिचालन का वर्णन है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा कि प्रगति और विकास के लिए साझेदारी भारत-श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों के सबसे मजबूत आधार स्तंभों में से एक है। उन्होंने कहा, 'हमारा विजन विकास को सभी तक ले जाना है, किसी को भी इससे वंचित नहीं रखना है।' श्री मोदी ने बताया कि श्रीलंका में भारत की सहायता से कार्यान्वित परियोजनाओं ने लोगों के जीवन को नया रूप दिया है। उन्होंने जानकारी दी कि उत्तरी प्रांत में आवास, जल, स्वास्थ्य और आजीविका सहायता से संबंधित कई परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और कांकेसनथुरई बंदरगाह के प्रगतिकरण के लिए समर्थन देने में प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, 'चाहे उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाली रेलवे लाइनों की बहाली हो; प्रतिष्ठित जाफना सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण; पूरे श्रीलंका में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा शुरू करना; डिक ओया में मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल हम 'सबका साथ, सबका विकास, सबका

> कनेक्टिविटी सिर्फ दो शहरों को साथ जोड़ने के बारे में नहीं है। यह देशों को नजदीक लाती है, हमारे लोग को नजदीक लाती हैं और हमारे दिलों को जोड़ती है।
>
> **श्री नरेन्द्र मोदी,** प्रधानमंत्री

विश्वास और सबका प्रयास' के विजन के साथ कार्य कर रहे हैं।'

हाल ही में भारत द्वारा आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के बारे में अपने विचार रखते हुए, प्रधानमंत्री ने वसुधैव कुटुम्बकम के भारत के दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला, जिसका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हार्दिक स्वागत किया है। उन्होंने रेखांकित किया कि इस दृष्टिकोण का एक भाग पड़ोसी देशों के साथ प्रगति और समृद्धि साझा करने को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे के शुभारंभ का भी उल्लेख किया और बताया कि यह एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी कॉरिडोर है जो पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रभाव का सृजन करेगा। उन्होंने बताया कि श्रीलंका के लोग भी इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संपर्क मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री ने नौका सेवा के सफल शुभारंभ के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति, सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया और साथ ही उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने रामेश्वरम और तलाईमन्नार के बीच नौका सेवा के पुनः आरंभ करने के बारे में भी बताया। ■

काउन्टर टेररिज्म के अप्रोच में जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटेजी व एक्शन को अपनाकर आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का समय आ गया है

देश के युवा पुलिस ऑफिसर्स देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, राज्यों में साइबर सुरक्षा का ऑडिट, सोशल मीडिया और वीजा की लगातार मॉनिटरिंग जैसे नए विषयों पर काम करें।

ब्यूरो

पिछले नौ वर्षों में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और नॉर्थ-ईस्ट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में काफी सुधार किया है। आने वाले पांच साल में और काम किए जाएंगे। आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह का कहना था कि आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा ठीक किए बिना दुनिया का कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। विकास के लिए पहली शर्त है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक हो।

अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि ये 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सम्मेलन अमृतकाल में हो रही पहली पुलिस विज्ञान कांग्रेस है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने ये लक्ष्य रखा है कि जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, उस वक्त विश्व में हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए हर क्षेत्र में परिश्रम की पराकाष्ठा करनी होगी और इसकी पहली शर्त है कि देश की कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा चाक-चौबंद हों। कोई भी देश जब तक अपनी आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा चाक-चौबंद नहीं करता, तब तक विकास नहीं हो सकता। कानून-व्यवस्था की अच्छी स्थिति ही विकास के लिए पहली शर्त है और इसके लिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में गृह मंत्रालय ने देश में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के अनेक परिवर्तन किए हैं। अमृतकाल में इन परिवर्तनों को जमीन पर उतार कर इनका सुफल देश को देने का समय है।

7 अक्टूबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह उत्तराखंड के देहरादून में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, श्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय गृह सचिव, श्री अजय कुमार भल्ला, केन्द्रीय गृह सचिव और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक, श्री बालाजी श्रीवास्तव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2019 से 2023 तक देश में हर क्षेत्र में कई बदलाव किए गए हैं। श्री शाह ने कहा कि इस पुलिस विज्ञान कांग्रेस के दौरान छह विषयों पर विचार विमर्श होगा- 5जी युग में पुलिसिंग, नारकोटिक्स- एक गेम चेंजिंग दृष्टिकोण, सोशल मीडिया की चुनौतियां, सामुदायिक पुलिसिंग, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां और पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बीच समन्वय-सीमाओं की सुरक्षा। पूर्वोत्तर की बात करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि हम नॉर्थ-ईस्ट को देश के दूसरे भागों से शांतिपूर्वक जोड़ने में सफल रहे हैं। 2019 से 2023 तक गृह मंत्रालय से लेकर स्थानीय पुलिस स्टेशन तक कानून व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस विज्ञान कांग्रेस का बहुत महत्व है क्योंकि यह अमृत काल की पहली पुलिस विज्ञान कांग्रेस है। इन 75 सालों में हमने लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की हैं। प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है कि जब हम आजादी के 100 साल मनाएं तो देश हर क्षेत्र में दुनिया में नंबर वन हो।

> प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। ऐसे में हमारे आर्थिक संस्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी देशभर की पुलिस और एजेंसियों को और मजबूती से निभानी होगी।
>
> **श्री अमित शाह**
> केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। ऐसे में हमारे आर्थिक संस्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी देशभर की पुलिस और एजेंसियों को और मजबूती से निभानी होगी। जब हर क्षेत्र में विकास होता है तब कई चुनौतियां भी हमारे सामने खड़ी होती हैं और उन चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए हमारी पुलिस को अपने आपको तैयार करना होगा। श्री शाह ने कहा कि देश के युवा पुलिस अधिकारियों को देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, राज्यों में साइबर सुरक्षा का ऑडिट, सोशल मीडिया और वीजा की लगातार मॉनिटरिंग जैसे नए विषयों पर काम करने की आवश्यकता है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि काउन्टर टेररिज्म के एप्रोच में जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटजी और जीरो टॉलरेंस एक्शन को अपनाकर आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का समय आ गया है। विभिन्न एजेंसियों के बीच राज्यों के पुलिसबलों को समन्वय बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ देशभर की पुलिस को जुड़ना चाहिए। मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो की स्टडी कर अपने यहां भी मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो बनाने की शुरूआत करें, डायरेक्टर प्रॉसीक्यूशन की व्यवस्था को और मजबूत करें, बीट को पुनर्जीवित करें, परेड को नियमित करें और खबरी प्रणाली को भी फिर से एक बार पुनर्जीवित करें। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस का एनालिसिस मानव दिमाग से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। इसके लिए खबरी प्रणाली को भी हमें पुनर्जीवित करना होगा। श्री शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित वाले फॉरवर्ड क्षेत्रों में बेस कैंप की स्थापना का जो प्रयास हो रहा है, उसमें वामपंथी उग्रवाद वाले राज्यों को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के लिए एनसीओआरडी मैकैनिज्म को मजबूत करना जरूरी है और इसके लिए एनसीओआरडी की जिला स्तरीय बैठक पर ध्यान देना होगा।■

केंद्रीय गृह मंत्री ने किया पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का विशेष उल्लेख

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के कम्पेन्डियम, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की प्रतिष्ठित हिन्दी पत्रिका (पुलिस विज्ञान) और उत्तराखंड पुलिस- मार्चिंग विद द टाइम्स पत्रिका का विमोचन हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को मजबूत करने के लिए विगत 5 सालों में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के चार्टर में समुद्री सीमा प्रबंधन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का क्षमता निर्माण, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, पुलिस की छवि और पुलिस समुदाय इंटरफेस के साथ और कई चीजों को जोड़ा गया है। स्वदेशी उपकरणों को विकसित करने के लिए एक अलग वर्टिकल खड़ा किया गया है और इसके लिए शोधकताओं, वैज्ञानिकों, प्रोफेसर, छात्रों और इंडस्ट्रीज के साथ एक सार्थक संवाद किया गया है। आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों और साधनों के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो के आधुनिकीकरण प्रभाग के अंतर्गत साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध रोकथाम, ड्रोन फॉरेंसिक, साइबर कानूनों की उभरती हुई चुनौतियां जैसे विषयों पर वेबिनार और कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

शहीदों के सपनों का भारत

गुजरात सरकार के युवा और सांस्कृतिक विभाग ने संपूर्ण गुजराती व्याकरण की पुस्तकों का एक पुस्तकालय बनाया है, बच्चों और युवाओ को इस पुस्तकालय की ओर लाने से गुजरात और पूरे देश का भविष्य संवरेगा।

ब्यूरो

आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर में 1857 से 1947 के 90 साल के आजादी के संग्राम में बलिदान देने वाले अनगिनत शहीदों के स्मारक बनाने, उनके इतिहास को पुनर्जीवित करने और युवा और नई पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिले, ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। 15 अक्टूबर, 2023 को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में 'समौ शहीदी स्मारक' एवं पुस्तकालय का लोकार्पण किया।

कार्यक्रम के दौरान संबोधन की शुरूआत में श्री अमित शाह ने कहा कि वे पिछली नवरात्रि के दौरान यहां आए थे और इस शहीदी स्मारक का भूमिपूजन किया था और आज पहले नवरात्र के दिन इस शहीद स्मारक का उद्घाटन हो गया है। उन्होंने कहा कि समौ में नवंबर, 1857 में आजादी के संघर्ष में 12 वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी लेकिन 2022-23 तक उनका कोई स्मारक नहीं था आज बना यह स्मारक उनकी शौर्य गाथाओं को अमर बनाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि गुजरात सरकार के युवा और सांस्कृतिक विभाग को उन शहीदों की याद में 12 स्तंभों वाला एक सुंदर स्मारक बनाना चाहिए, जिससे हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब ध्वजारोहण हो, तब उन शहीदों का भी सम्मान हो। इसके साथ ही देश के इतिहास, भाषा और संस्कृति के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए एक पुस्तकालय भी बनना चाहिए।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि गुजरात सरकार के युवा और सांस्कृतिक विभाग ने संपूर्ण गुजराती व्याकरण की पुस्तकों का एक पुस्तकालय बनाया है, जिसके लिए वे अभिनंदन के पात्र हैं। विद्यार्थियों, युवाओं और बच्चों को इस पुस्तकालय की ओर मोड़ने की ज़िम्मेदारी शिक्षकों की है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को जिस विषय में उनकी रुचि हो, उस विषय का ज्ञानी बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, जिससे गुजरात और देश को एक अच्छा नागरिक मिलेगा। उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी ने यहां वांचे गुजरात अभियान शुरू किया था और उस समय पूरे गुजरात के सभी पुस्तकालयों को समृद्ध करने की योजना बनाई थी। उसी प्रेरणा से समौ गांव के पुस्तकालय को बनाया गया है। इसके साथ ही 100 विद्यार्थियों के पढ़ने की सुविधा यहां उपलब्ध कराई गई है।

श्री अमित शाह ने समौ के युवाओं से कहा कि सरकार सुविधा उपलब्ध करवा सकती है, लेकिन उन सुविधाओं की देखरेख का काम ग्रामीणों और स्थानीय युवाओं को करना होगा। लगभग दो करोड़ रूपए के खर्च से एक सुंदर बाग, शहीद स्मारक और पुस्तकालय गुजरात सरकार ने बनाया है इनकी देखभाल के लिए युवाओं की एक समिति बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर युवा इस जिम्मेदारी को नहीं उठाएंगे तो यह पूरी व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं चल सकेगी। अगर युवा इस जिम्मेदारी को उठाएंगे तो यह उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ■

> **श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वांचे गुजरात अभियान शुरू किया था और उस समय पूरे गुजरात के सभी पुस्तकालयों को समृद्ध करने की योजना बनाई थी, उसी प्रेरणा से समौ गांव के पुस्तकालय को बनाया गया है।**
>
> **श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

सबसे पहले देश

सरकार की नीतियों में जब जनता के हितों की बात सबसे पहले होती है, तो उसमें सबकी भागीदारी होती है। प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और साथ लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए सभी केंद्रीय गृहराज्य मंत्री लगातार सक्रिय दिख रहे हैं।

ब्यूरो

13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय सशस्त्र सीमा बल 47वीं वाहिनी रक्सौल, धुपवा टोला बीओपी में 'मेरी माटी, मेरा देश' अभियान के अंतर्गत चंपारण के 27 ब्लॉक के 1,277 गांवों में वीर शहीदों के घर से मिट्टी एकत्रित कर अमृत कलश यात्रा में सम्मिलित हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में शहीद वीर-वीरांगनाओं के सम्मान में देशभर में 'मेरी माटी, मेरा देश' अभियान के तहत अमर बलिदानियों की स्मृति में देश के कोने-कोने से अमृत कलश यात्रा निकाली जा रही है। यह अभियान देश को गुलामी की मानसिकता को खत्म करने, हमारी समृद्ध विरासत पर गर्व करने और देश में एकता को बढ़ावा देने वाला सिद्ध हो रहा है।

कार्यक्रम में बेतिया सांसद डॉ संजय जसवाल, उप महानिरीक्षक प्रेषक मुख्यालय बेतिया श्री सुरेश सुब्रमण्यम, कमांडेंट श्री गुरबिंदरजीत सिंह, कमांडेंट 47वीं वाहिनी रक्सौल श्री विकास, द्वितीय कमान अधिकारी रक्सौल श्री आनेंद्र मनी, सीओ रक्सौल श्री विजय कुमार, एसडीपीओ रक्सौल श्री धीरेंद कुमार, सशस्त्र सीमा बल के जवान, सीमा मित्र एवं अन्य लोग रहे। इससे एक दिन पहले 12 अक्टूबर को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय ने सशस्त्र सीमा बल 44वीं वाहिनी नरकटियागंज की सीमा चौकी तीन लालटेन के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया और सैनिक सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे।

8 अक्टूबर को सिक्किम दौरे के दूसरे दिन गृह राज्यमंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा ने सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। श्री अजय कुमार मिश्रा ने तेजी से और प्रभावी रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। साथ ही सिक्किम के मुख्यमंत्री ने त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया और पुनर्प्राप्ति और बहाली कार्य में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा ने मंगन जिले के नागा में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित नागरिकों को राहत और सहायता का आश्वासन दिया और इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। श्री मिश्रा ने पृथक क्षेत्रों में फंसे व्यक्तियों के लिए बचाव और राहत प्रयासों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

9 अक्टूबर को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री निशीथ प्रमाणिक ने पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में आयोजित अमृत कलश यात्रा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मां भारती के वीर सपूतों को, हमारे शहीदों को सम्मान देने की दिशा में शुरू हुए 'मेरी माटी मेरा देश' कार्यक्रम के तहत देश-भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है।

चार वर्षों में आई वामपंथी उग्रवाद में कमी

भारत के समक्ष असंख्य चुनौतियां हैं, जो देश के कई राज्यों की आंतरिक सुरक्षा, विकास और सामाजिक शांति के लिए खतरा पैदा करती हैं। इनमें से वामपंथी उग्रवाद का मुद्दा अहम है। इसे आम बोलचाल की भाषा में नक्सलवाद या माओवाद कहा जाता है। वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में एक छोटे से किसान विद्रोह से शुरू हुआ है यह आंदोलन, जो वैचारिक उग्रवाद के बल पर भारत के पहाड़ी आदिवासी इलाकों में फैल गया। समर्थकों ने तर्क दिया कि वे 1970 और 1980 के दशक की शुरूआत में प्रचलित दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग के लिए लड़ रहे थे, उनकी रणनीति-हिंसा और धमकी से प्रभावित-उन समुदायों को और अधिक अलग-थलग करने और आघात पहुंचाने में काम आई, जिनका वे प्रतिनिधित्व करने का दावा करते थे।

दुर्गा प्रसाद कोड़े

यह खतरा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधिकार क्षेत्र तक फैला हुआ है और कई प्रशासनिक सीमाओं के पार आम नागरिकों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। ऐसे में एक सूक्ष्म दृष्टिकोण समय की आवश्यकता थी। जबकि कुछ राज्यों ने समाधान खोजने और बढ़त हासिल करने के लिए आक्रामक, रक्षात्मक और विकासात्मक रणनीतियों को सक्रिय रूप से अपनाया। कुछ अन्य ने इन राज्यों के अनुभव से सीखा और एक साथ काम कर रहे थे। 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय का नेतृत्व करने के बाद केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह जी आगे आए और माओवादी विद्रोह से प्रभावित राज्य सरकारों के परामर्श से इन प्रयासों का समन्वय किया। उन्होंने नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा की और राज्य सरकारों और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों को संश्लेषित करते हुए चरमपंथियों के खिलाफ एक सुविचारित दृष्टिकोण का नेतृत्व किया। परिणाम बेहद उत्साहजनक और संतोषजनक रहे और नक्सल प्रभावित राज्यों में चरमपंथी गतिविधियों में तेजी से गिरावट देखी गई।

सुरक्षा-उन्मुख दृष्टिकोण, जैसे-विशेष बलों की तैनाती और खुफिया-संचालित ऑपरेशन, माओवादी खतरे का मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार की रणनीति की आधारशिला रहे हैं। हालांकि आक्रामक होने के लिए आलोचना की गई, लेकिन इन उपायों से निर्विवाद सफलता मिली है, क्योंकि प्रमुख चरमपंथी नेताओं को या तो पकड़ लिया गया है या खत्म कर दिया गया है। नतीजतन पिछले चार वर्षों में वामपंथी उग्रवाद की भौगोलिक उपस्थिति में कमी आई है।

सिर्फ पुलिस की कार्रवाई ही वामपंथी खतरे कर मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, इसलिए केंद्र सरकार के समर्थन से राज्य सरकारों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के उद्देश्य से कई पहल आरंभ की है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए समर्पित सुरक्षा संबंधी निधि के अलावा, कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की गई, संचार और सड़क संपर्क में सुधार किया गया, स्कूलों का निर्माण किया गया और पहले दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया। जन-धन योजना जैसी वित्तीय समावेशन योजनाओं ने भी हाशिए पर रहने वाले समुदायों को आर्थिक मुख्यधारा में लाने में मदद की। रोजगार के क्षेत्र में युवाओं के लिए आदिवासी क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए।

सरकार ने पुनर्वास पैकेजों के साथ आत्मसमर्पण करने और नागरिक जीवन में शामिल होने के लिए पर्याप्त अवसर और रास्ते प्रदान करके नक्सलियों को हथियार डालने के लिए प्रोत्साहित किया। इन नीतियों ने न केवल चरमपंथी समूहों के लिए उपलब्ध जनशक्ति को कम कर दिया है, बल्कि निराश और असंतुष्ट कैडरों को एक संदेश भी भेजा है कि मुख्यधारा के समाज में पुनः शामिल होना बहुत संभव है। कमजोर होता नेतृत्व, घटता वैचारिक उत्साह, कम होती भर्तियां, बढ़ता पलायन, हथियारों और गोला-बारूद की आपूर्ति में अत्यधिक बाधाएं और इसी तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों ने नक्सलियों के प्रभाव और तबाही मचाने की उनकी क्षमता को और कम कर दिया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि संबंधित राज्यों में पुलिस की भूमिका और अशांत क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती से कानून और व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों को बल मिला है। इससे वामपंथी चरमपंथियों के हिंसक कृत्यों से प्रभावित स्थानीय आबादी तक आवश्यक नागरिक सेवाओं की डिलीवरी में भी सुविधा हुई है। लोगों के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के माध्यम से आम जनता, खासकर युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के दिल और दिमाग को जीतने में कामयाब रहा है।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की इकाइयों ने सुरक्षा से परे पहल की है। इसमें शामिल हैं- फील्ड अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल का विस्तार, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और खेल प्रोत्साहन के माध्यम से नौकरी के अवसरों को बढ़ाने के लिए कौशल विकास - साथ ही बीज, उर्वरक के माध्यम से कृषि कार्यों में सहायता प्रदान करना और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में ट्रैक्टर भी। इस उल्लेखनीय पहल से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के माध्यम से उन्होंने बुजुर्गों, बच्चों, गरीबों और विकलांगों की सहायता की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने जरूरतमंद लोगों को खेती के उपकरण, सिलाई मशीन, साइकिल, बर्तन, ट्रांजिस्टर, छाते और कपड़े जैसी कई आवश्यक वस्तुएं भी प्रदान की हैं। इस तरह की मानवीय गतिविधियों ने सामुदायिक लचीलेपन की भावना को बढ़ावा देते हुए गरीब ग्रामीणों की आर्थिक कमजोरियों को संबोधित किया है।

(पूर्व महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल)

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 'पुलिस और सेवा' यू ट्यूब चैनल में बताया गया है कि सशस्त्र सीमा बल अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ खेलों में भी गौरवशाली इतिहास रच रहा है। बल में खेल प्रमुख गतिविधियों में से एक है, जो बल कर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाता है। साथ-साथ उन्हें किसी भी विषम परिस्थितियों से निपटने में निपुण बनाता है। बल को उम्मीद है कि उसके खिलाड़ी भविष्य में ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन खेलों में देश और बल का नाम रोशन करेंगे।

राज्य विशेष बलों के साथ एनएसजी स्थापना दिवस काउंटर टेररिज्म सेमिनार के साथ संपन्न हुआ। इस सेमिनार ने विशेष बलों को बहु-शहर, बहु-लक्षित आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए विशेषज्ञता, रणनीति और रणनीतियों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। इस अवसर पर आईबी प्रमुख श्री तपन कुमार डेका मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा महानिदेशक, श्री बालाजी श्रीवास्तव के नेतृत्व में गांव सभा के प्रधान के सौजन्य से इंद्र कैंप तथा रंगपुरी पहाड़ी, वसंत कुंज में 1 घंटे का स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिसमें ब्यूरो के अधिकारी एवं कार्मिकों के साथ-साथ उस क्षेत्र के आम जन के साथ मिलकर बापू को स्वछांजलि दी।

आईटीबीपी द्वारा राष्ट्रीय पुलिस स्मारक, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में आयोजित एक स्मृति कार्यक्रम के दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उच्च अधिकारियों के साथ-साथ अनेक बल कर्मियों ने अपने देशवासियों की भलाई के लिए स्वेच्छा से रक्तदान किया।

भारत के वीर

देश के जवानों को श्रद्धांजलि और समर्थन https://bharatkeveer.gov.in

दिशा-निर्देश

- आप सीधे भारत के वीर के खाते में (अधिकतम ₹15 लाख तक) दान कर सकते हैं या भारत के वीर कोष में दान कर सकते हैं।
- अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, प्रति वीर ₹15 लाख की सीमा तय की गई है और यदि राशि ₹15 लाख से अधिक है तो दाता को सतर्क किया जाएगा, ताकि वे या तो अपने योगदान को कम करने या योगदान के हिस्से को किसी अन्य भारत के वीर के खाते में डालने का विकल्प चुन सकें।
- भारत के वीर फंड का प्रबंधन प्रतिष्ठित व्यक्तियों और समान संख्या में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो आवश्यकता के आधार पर भारत के वीर परिवार को समान रूप से फंड वितरित करने का निर्णय लेंगे।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के लिए फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित व विबा प्रेस प्रा.लि.,नई दिल्ली द्वारा मुद्रित

दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए जन-भागीदारी से बेहतर माध्यम नहीं हो सकता। मेरा हमेशा से ही मानना रहा है कि सरकारें बहुमत से बनती हैं, पर देश सहमति से चलता है। डिबेट और डेलिब्रेशन्स से इस दुनिया को बेहतर बनाने के हमारे प्रयास जरूर सफल होंगे।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

सत्यमेव जयते

BPRD

आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037